IJAER/ July-August 2017/Volume-6/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# मानवाधिकार और मानवाधिकार संगठन

**डॉ मंजुलता शर्मा**

**व्याख्याता-राजनीति विज्ञान**

**राजकीय महाविद्यालय निवाई टोंक राजस्थान**

मानव अधिकार वस्तुत: वे अधिकार माने जाते हैं जो किसी भी मानव को मानव होने के नाते नैसर्गिक रूप से प्राप्त होने चाहिए। मानव रूप में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है।ये अधिकार अधिकार मानव की गरिमा और अस्मिता से जुड़े हैं इसलिए ये अधिकार बिना किसी जाति, लिंग और वय का भेद किए हर एक मानव को प्राप्त होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि मानव अधिकार वस्तुतः मानव होने के नाते उसको प्राप्त प्राकृतिक अधिकार है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार सरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत की गयी। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह सविंधान द्वारा अभिनिश्चित तथा अन्तरराष्ट्रीय सन्धियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। यह एक बहु सदस्यीय निकाय है। इसके प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे।इसके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष (जो भी पहले पूर्ण हो जाए)। इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक गठित समिति की सिफारिश पर होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धान्तों के अनुरूप है जिन्हें अक्तूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा 20 दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था।

**प्रमुख शब्द:** *मानवाधिकार, संगठन*

## परिचय

मानवाधिकार मानदंडों और उन मानदंडों के प्रवर्तन के बीच मौजूदा अंतर मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए काम करने के लिए मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठनों एमएल(NGOs1) के लिए जगह प्रदान करता है। वैश्वीकरण से जुड़े परिवर्तनों ने मानवाधिकार एनजीओ की भूमिका को मजबूत किया है और आज, जैसा पहले कभी नहीं था, वे मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने वाले सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों में से एक हैं। मानवाधिकारों के क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की बढ़ती भूमिका मानव अधिकारों के कुशल संरक्षण और राज्य पर उनके प्रभाव के बारे में कई सवाल उठाती है, जो संप्रभुता के संदर्भ में, अपने नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, इस निर्णय पर एक आवश्यक एकाधिकार बनाए रखता है। फिर भी, मानवाधिकारों की सुरक्षा की समग्र प्रक्रिया और राज्य के व्यवहार पर इन गैर-राज्य अभिनेताओं के प्रभाव का पूरी तरह से आकलन नहीं किया गया है। प्रश्न अभी भी बने हुए हैं, और आगे एनजीओ गतिविधियों के प्रभाव का पता लगाने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। यह लेख मानवाधिकार एनजीओ द्वारा निभाई गई दोहरी भूमिका का विश्लेषण करता है, जो मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं और जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की भाषा, संस्थानों और मानदंडों पर पूरी तरह या आंशिक रूप से भरोसा करते हैं।

## एनजीओ क्या हैं?

गैर-सरकारी या गैर-लाभकारी शब्द का प्रयोग आम तौर पर उन संगठनों की श्रेणी को कवर करने के लिए किया जाता है जो नागरिक समाज बनाने के लिए जाते हैं। ऐसे संगठनों की विशेषता, सामान्य रूप से, उनके अस्तित्व के उद्देश्य के रूप में वित्तीय लाभ के अलावा कुछ और होती है। हालांकि, यह अस्तित्व और उद्यमों और गतिविधियों की एक विस्तृत विविधता

के लिए बहुत सारे कारण छोड़ देता है। एनजीओ छोटे दबाव समूहों से लेकर, उदाहरण के लिए, विशिष्ट पर्यावरणीय चिंताओं या विशिष्ट मानवाधिकारों के उल्लंघन, शैक्षिक दान, महिलाओं के शरणार्थियों, सांस्कृतिक संघों, धार्मिक संगठनों, कानूनी नींव, मानवीय सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से - और सूची जारी रह सकती है - सभी तरह से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सैकड़ों या हजारों शाखाओं या सदस्यों वाले विशाल अंतरराष्ट्रीय संगठन। इस खंड में, हम संक्षेप में उस महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हैं जो ऐसे संगठनों के पास है और दुनिया भर में मानवाधिकारों की सुरक्षा में है। व्यक्तिगत नागरिकों की गरिमा को बनाए रखने के विभिन्न प्रयासों के लगभग हर स्तर पर जब इसे राज्य की शक्ति से खतरा होता है, तो गैर-सरकारी संगठन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं:

- सीधे तौर पर या प्रासंगिक अदालतों के माध्यम से विशेष 'परीक्षण मामलों' का समर्थन करके मानवाधिकारों के व्यक्तिगत उल्लंघनों से लड़ना
- जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है उन्हें सीधे सहायता की पेशकश करना
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतरराष्ट्रीय कानून में बदलाव के लिए पैरवी करना
- उन कानूनों के सार को विकसित करने में मदद करना
- आबादी के बीच मानव अधिकारों के बारे में ज्ञान और सम्मान को बढ़ावा देना।

गैर-सरकारी संगठनों का योगदान न केवल प्राप्त परिणामों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, और इसलिए दुनिया में मानवाधिकारों की रक्षा के बारे में लोग जो आशावाद महसूस कर सकते हैं, बल्कि इसलिए भी कि गैर-सरकारी संगठन बहुत ही प्रत्यक्ष अर्थों में ऐसे उपकरण हैं जो दुनिया भर में व्यक्तियों और समूहों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए उपलब्ध हैं। वे प्रबंधित और समन्वित हैं - जितने भी संगठन हैं - निजी व्यक्तियों द्वारा, लेकिन वे अपनी ताकत का एक बड़ा हिस्सा समुदाय के अन्य सदस्यों से भी लेते हैं जो उनके कारण स्वैच्छिक समर्थन की पेशकश करते हैं। यह तथ्य उन्हें उन व्यक्तियों के लिए बहुत महत्व देता है जो दुनिया में मानवाधिकारों के सुधार में योगदान देना चाहते हैं।

**मानवाधिकार एनजीओ के प्रकार**

मानवाधिकारों पर 1993 के संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन - जिसे वियना सम्मेलन के रूप में जाना जाता है - में दुनिया भर के 841 गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया, जिनमें से सभी ने खुद को मानवाधिकार मिशन के साथ काम करने वाला बताया। हालांकि यह अपने आप में एक प्रभावशाली आंकड़ा है, यह वास्तव में दुनिया में सक्रिय मानवाधिकार एनजीओ की कुल संख्या का केवल एक छोटा अंश दर्शाता है।

अधिकांश स्वयंभू "मानवाधिकार संगठन" नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के संरक्षण में लगे हुए हैं। कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसे संगठनों में सबसे प्रसिद्ध में एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स फर्स्ट और इंटराइट्स शामिल हैं। हालाँकि, जैसा कि हमने देखा है, नागरिक और राजनीतिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त कई अलग-अलग मानवाधिकारों में से केवल एक श्रेणी हैं, और नए अधिकार आज भी सामने आ रहे हैं। जब हम इसे ध्यान में रखते हैं और गरीबी, हिंसा, जातिवाद, स्वास्थ्य समस्याओं, बेघरों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का मुकाबला करने में सक्रिय गैर-सरकारी संगठनों पर विचार करते हैं, तो मानव अधिकार संरक्षण में लगे गैर-सरकारी संगठनों की वास्तविक संख्या, एक या दूसरे रूप में, दुनिया भर में सैकड़ों हजारों में चलता है।

**वे प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करते हैं?**

एनजीओ विभिन्न चरणों या स्तरों पर मानवाधिकारों के संरक्षण में संलग्न होने का प्रयास कर सकते हैं, और उनके द्वारा नियोजित रणनीतियाँ उनके उद्देश्यों की प्रकृति के अनुसार अलग-अलग होंगी - उनकी विशिष्टता या सामान्यता; उनकी दीर्घकालिक या अल्पकालिक प्रकृति; उनका स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय दायरा, और इसी तरह।

**प्रत्यक्ष सहायता**

सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के लिए यह विशेष रूप से आम है कि वे मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार लोगों को किसी प्रकार की सीधी सेवा प्रदान करते हैं। ऐसी सेवाओं में नए कौशल विकसित करने के लिए मानवीय सहायता, संरक्षण या प्रशिक्षण के रूप शामिल हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, जहां अधिकार कानून द्वारा संरक्षित है, वे कानूनी वकालत या दावों को प्रस्तुत करने के तरीके पर सलाह शामिल कर सकते हैं। हालांकि, कई मामलों में, उल्लंघन के शिकार या मानवाधिकार रक्षक को सीधी सहायता या तो संभव नहीं है या किसी संगठन के संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऐसे अवसरों पर, और यह संभवतः अधिकांश मामलों का प्रतिनिधित्व करता है, गैर-सरकारी संगठनों को एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेने और उल्लंघन को सुधारने या भविष्य में इसी तरह की घटनाओं को रोकने के अन्य तरीकों के बारे में सोचने की आवश्यकता है।

**सटीक जानकारी जुटा रहा है**

यदि एनजीओ सक्रियता के विभिन्न रूपों के आधार पर कोई मौलिक रणनीति है, तो शायद यह अन्याय के अपराधियों को "दिखाने" का प्रयास करने का विचार है। सरकारें बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय संधियों, या अन्य अधिकार मानकों के तहत अपने दायित्वों से बचने में सक्षम होती हैं, क्योंकि उनकी नीतियों के प्रभाव को आम जनता नहीं जानती है। इस तरह की जानकारी एकत्र करना और सरकारों के मानवाधिकार रिकॉर्ड में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग करना उन्हें जिम्मेदार ठहराने के लिए आवश्यक है और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अक्सर इसका उपयोग किया जाता है।

वे एक ऐसे मुद्दे की पहचान करके लोगों या सरकारों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं जो लोगों की अन्याय की भावना को अपील करेगा और फिर इसे सार्वजनिक करेगा।

संगठनों के दो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण जो अपनी सटीक निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए प्रतिष्ठित हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति हैं। इन दोनों संगठनों के पास न केवल आम जनता के बीच बल्कि संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी अधिकार है, जहाँ उनकी रिपोर्ट को उन सरकारों की निगरानी की आधिकारिक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में ध्यान में रखा जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों की शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।

**प्रचार और पैरवी**

नीति परिवर्तन लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता अक्सर अभियान और वकालत में संलग्न होते हैं। फिर से, कई रूप हैं, और एक एनजीओ अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, अपने "लक्ष्य" की प्रकृति और निश्चित रूप से, अपने स्वयं के उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए, सबसे उपयुक्त को अपनाने की कोशिश करेगा। कुछ सामान्य अभ्यासों की रूपरेखा नीचे दी गई है।

- पत्र-लेखन अभियान एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा बड़े प्रभाव के लिए किया गया है। लोग और संगठन पूरी दुनिया में अपने हजारों सदस्यों के पत्रों के साथ सरकारी अधिकारियों पर "बमबारी" करते हैं।

- स्ट्रीट एक्शन या प्रदर्शन, मीडिया कवरेज के साथ जो सामान्य रूप से आकर्षित होते हैं, का उपयोग तब किया जा सकता है जब संगठन जनता के समर्थन को सूचीबद्ध करना चाहते हैं या किसी सरकार को 'नाम और शर्म' करने के लिए जनता की नज़र में कुछ लाना चाहते हैं।
- मीडिया अक्सर लॉबीइंग प्रथाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और सोशल मीडिया और इंटरनेट अब तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर रहे हैं।
- किसी विशेष देश में मानवाधिकारों के आनंद के संबंध में वास्तविक स्थिति का एक एनजीओ परिप्रेक्ष्य देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार निगरानी निकायों को छाया रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

समर्थन या सार्वजनिक आक्रोश के प्रदर्शनों के अलावा, एनजीओ अधिकारियों के साथ निजी बैठकों या ब्रीफिंग में भी शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी जनता की नज़रों में कुछ लाने की धमकी नीति या व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त हो सकती है, जैसा कि नीचे दी गई कहानी में है। जबकि यह एक समय में टेप, पोस्टर और फैक्स के माध्यम से जुटाया जाता था, अब इसे ईमेल अभियानों और याचिकाओं, इंटरनेट साइटों, ब्लॉगों और इलेक्ट्रॉनिक सोशल नेटवर्क के माध्यम से जुटाया जाता है।

सामान्य तौर पर, जनता या अन्य प्रभावशाली अभिनेताओं (उदाहरण के लिए, अन्य सरकारों) से जितना अधिक समर्थन होता है, उतनी ही अधिक संभावना होती है कि एक अभियान अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेगा। यहां तक कि अगर वे हमेशा सीधे इस समर्थन का उपयोग नहीं करते हैं, तो एनजीओ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका संदेश केवल यह संकेत देकर सुना जाए कि एक सरकार या कई सरकारों के खिलाफ एक बड़ा लोकप्रिय आंदोलन चलाया जा सकता है।

**मानवाधिकार शिक्षा और जागरूकता**

कई मानव अधिकार एनजीओ भी शामिल हैं, कम से कम उनकी गतिविधियों के हिस्से के रूप में, कुछ प्रकार की सार्वजनिक जागरूकता या शैक्षिक कार्य। यह महसूस करते हुए कि उनके समर्थन का सार आम जनता के पास है, एनजीओ अक्सर जनता के सदस्यों के लिए मानवाधिकारों के मुद्दों का अधिक से अधिक ज्ञान लाने का प्रयास करेंगे। इन मुद्दों और उनके बचाव के तरीकों का अधिक ज्ञान एक बड़ा सम्मान पैदा करने की संभावना है और बदले में, मानव अधिकारों के उल्लंघन के विशेष मामलों में समर्थन जुटाने में सक्षम होने की संभावना बढ़ जाएगी। यह वह समर्थन, या संभावित समर्थन है, जो मानव अधिकारों के वातावरण को बेहतर बनाने में एनजीओ समुदाय की सफलता का आधार है।

**सफल सक्रियता के उदाहरण**

**आवास अधिकार और निष्कासन केंद्र (COHRE)**

यह मानवाधिकार संगठन 1994 में आवास अधिकारों की सुरक्षा और दुनिया भर में जबरन बेदखली की रोकथाम के लिए काम करने के लिए स्थापित किया गया था। कोहे "आवास" की अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की समझ का उपयोग करता है, जिसका अर्थ है किसी के सिर पर छत से अधिक। कोहे ने जोर देकर कहा है कि "दुनिया की लगभग आधी आबादी के पास वर्तमान में पर्याप्त आवास तक पहुंच नहीं है जो कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत गारंटीकृत है"। पर्याप्त आवास अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, COHRE और दुनिया भर में इसके सहयोगी निम्नलिखित के संबंध में विश्लेषण, वकालत, सार्वजनिक शिक्षा, प्रशिक्षण और मुकदमेबाजी कार्य प्रदान करते हैं:

- जबरन बेदखली

- कार्यकाल की सुरक्षा
- भूमि तक पहुंच
- पानी और सफ़ाई व्यवस्था
- महिला और आवास अधिकार
- मुकदमेबाजी और कानूनी वकालत
- पुनर्स्थापन और वापसी
- आवास अधिकारों पर मेगा आयोजनों का प्रभाव।

नवंबर 2010 में एक ऐतिहासिक निर्णय में, COHRE बनाम इटली में, यूरोप की सामाजिक अधिकारों की समिति की परिषद (संशोधित यूरोपीय सामाजिक चार्टर की निगरानी) ने पाया कि इटली ने रोमा शिविरों के विनाश के कारण अपनी रोमा आबादी के अधिकारों का उल्लंघन किया है और बेदखली और इटली से रोमा का निष्कासन। गैर-इतालवी रोमा, जो अन्य यूरोपीय संघ के राज्यों के नागरिक हैं, के इन सामूहिक निष्कासनों में 2008 के बाद नाटकीय रूप से वृद्धि हुई थी। उल्लंघन के संबंध में पाए गए: पर्याप्त आवास के लिए रोमा लोगों के अधिकारों का भेदभाव और उल्लंघन; सामाजिक, कानूनी और आर्थिक सुरक्षा; गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से सुरक्षा; और प्रवासी रोमा परिवारों के संरक्षण और सहायता का अधिकार। इटली की नीतियों और प्रथाओं, जो रोमा निवासियों को पृथक और अत्यधिक अपर्याप्त आवास स्थितियों में रहने के लिए छोड़ देते हैं, की भी आलोचना की गई।

**मानवाधिकार एनजीओ का मानव अधिकारों के संरक्षण पर प्रभाव**

एक व्यापक दृष्टिकोण है कि मानवाधिकार एनजीओ4 परोपकारी संगठन हैं जो मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के दुरुपयोग को रोकने के लिए काम करते हैं। मानवाधिकारों की रक्षा में कई एनजीओ अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मानदंडों द्वारा निर्देशित होते हैं जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948), नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (1966), आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध में शामिल हैं। (1966) और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियाँ। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार कानून (उदाहरण के लिए, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए यूरोपीय सम्मेलन और अन्य) का भी बहुत महत्व है। गैर-सरकारी संगठनों के हाथों में ये मानवाधिकार मानदंड (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय) अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण बन जाते हैं - दुनिया भर में सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए। एनजीओ मानवाधिकारों के हनन को रोकने की कोशिश करते हैं और कई अलग-अलग तरीकों से कार्य करके सरकारों और अन्य अभिनेताओं के उल्लंघन के खिलाफ मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत और संयुक्त राष्ट्र की शुरुआत से, गैर-सरकारी संगठन मानवाधिकार मानकों के विकास में सक्रिय रूप से शामिल थे। जैसा कि विलियम कोरी कहते हैं, "अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना जिसके द्वारा राज्यों के आचरण को मापा या आंका जा सकता है - गैर-सरकारी संगठनों का प्राथमिक व्यवसाय था"। 5 कई मामलों में, मानवाधिकार एनजीओ नए मानवाधिकार दस्तावेजों के आरंभकर्ता थे, यानी वे जो मानवाधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियम स्थापित करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्य मानवाधिकार दस्तावेजों के प्रारूपण में भाग लिया: मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948), बाल अधिकारों पर कन्वेंशन (1989) और कई अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मानवाधिकार संधियाँ। मानवाधिकार मानकों को स्थापित करने में एनजीओ योगदानकर्ताओं की भूमिका भी निभाते हैं। मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया में वे कानूनों और संधियों को लिखने में मदद करते हैं और बड़े पैमाने पर राजनेताओं के बजाय मानवाधिकारों के विशेष क्षेत्र के विशेषज्ञों के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि क्लॉड इमर्सन वेल्च ने लिखा है, "यह भूमिका बढ़ी और राजनीतिक हो गई क्योंकि एनजीओ ने वैधता प्राप्त की, अंतरराष्ट्रीय जनमत को आकार दिया और सहानुभूतिपूर्ण सरकारों के साथ गठबंधन बनाया"।

एनजीओ शिकायतों के प्रस्तुतीकरण और अंतरराष्ट्रीय मुकदमेबाजी के माध्यम से, पार्टियों के रूप में मामलों में हस्तक्षेप करने, विशेषज्ञों के रूप में सेवा करने, गवाहों के रूप में गवाही देने आदि के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसके अलावा, "कई मामलों में एनजीओ ने न केवल प्रासंगिक मानदंडों के लिए आम सहमति बनाने और निर्माण करने में शामिल है, बल्कि उन मानदंडों को लागू करने के लिए डिज़ाइन किए गए संस्थानों को स्थापित करने में भी मदद करता है"। मानवाधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए हमेशा मानवाधिकारों की शर्तों और लागू कानूनी सिद्धांतों के अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है।

एनजीओ दुनिया भर में विशेष देशों में मानवाधिकार स्थितियों की लगातार निगरानी करते हैं (बाद वाले को ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे ट्रांसनेशनल एनजीओ पर लागू किया जाता है)। वे यह भी निगरानी करते हैं कि राज्य मानवाधिकार कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करते हैं या नहीं। दूसरे शब्दों में, वे "प्रहरी" के रूप में कार्य करते हैं और एक स्वतंत्र अवलोकन और मूल्यांकन प्रदान करते हैं कि क्या और कैसे मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं। ऐसी निगरानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार स्थितियों के बारे में डेटा एकत्र करने और किसी भी समस्या को उजागर करने में मदद करती है। एनजीओ मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के दुरुपयोग के संबंध में जानकारी एकत्र करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। वे विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्र करते हैं: उदाहरण के लिए, मानवाधिकार पीड़ितों, गवाहों, अन्य मानवाधिकार गैर सरकारी संगठनों, समाचार पत्रों से, चोटों और भौतिक साक्ष्यों की जांच करने, परीक्षणों और प्रदर्शनों को देखने में। मानवाधिकारों के मुद्दों के बारे में जानकारी एकत्र करने और प्रसारित करने से एनजीओ जनता, सरकारों और अन्य अभिनेताओं का ध्यान मानव अधिकारों के क्षेत्र में मौजूद समस्याओं की ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं और आम तौर पर अनसुनी आवाज़ों की चिंताओं को उठाते हैं। इस प्रकार मानव अधिकार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सूचना की जाँच, प्रलेखन और प्रसार मानव अधिकारों के हनन को सार्वजनिक और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के ध्यान में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसा कि क्लॉड इमर्सन वेल्च ने नोट किया है, "गैर-सरकारी संगठनों [सूचना, दस्तावेज़ीकरण और डेटा के प्रवाह] के बिना संपूर्ण मानव अधिकार कार्यान्वयन प्रणाली और संयुक्त राष्ट्र रुक जाएगा"। सूचना एकत्र करने में गैर-सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को थियो वैन बोवन ने भी मान्यता दी है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार केंद्र के पूर्व निदेशक के अनुसार, एनजीओ केंद्र को प्रदान की जाने वाली जानकारी का 85 प्रतिशत प्रदान करते हैं और इस प्रकार यह साबित करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सूचना के लिए एनजीओ पर काफी निर्भर है। दरअसल, एनजीओ सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, राजनेताओं, मानवाधिकार न्यायाधिकरणों के लिए सूचना के प्रमुख स्रोत के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा, एनजीओ विश्वसनीय और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं जो कभी-कभी राज्यों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का खंडन करती है, और इस प्रकार यह साबित करती है कि कुछ देश अपने देश में वास्तविक मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में झूठ बोल सकते हैं। मानवाधिकारों के संबंध में गैर-सरकारी संगठन "नीति को बदलने के लिए सरकारों की पैरवी करने में उनका प्रमुख हथियार" इकट्ठा, सत्यापित और प्रसारित करते हैं।

"अधिवक्ताओं" की भूमिका निभाते हुए, एनजीओ राजनेताओं को बेहतर और अधिक कुशल मानवाधिकार संरक्षण के पक्ष में निर्णय लेने के लिए प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। बड़े हिस्से में पैरवी नए मानवाधिकार मानकों पर वार्ता या परामर्श प्रक्रियाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से होती है। एनजीओ मानवाधिकारों के उल्लंघनकर्ता राज्यों के संबंध में कुछ कार्रवाई करने के लिए क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी निकायों की पैरवी भी करते हैं। इस प्रकार एनजीओ लॉबिंग का एक आंतरिक और साथ ही बाहरी आयाम है। यह उल्लेखनीय है कि परंपरागत रूप से मानव अधिकार गैर सरकारी संगठनों के काम में, सूचनाओं का संग्रह उन कारणों (उदाहरण के लिए, पारंपरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आर्थिक विकास और आदि) की खोज करने के बजाय सरकार द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन पर केंद्रित है जो उन्हें रेखांकित करते हैं। एक डर मौजूद है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन क्यों होते हैं, यह समझाने से सरकारों को

न्यायोचित ठहराया जा सकता है या उन दावों को बल मिल सकता है कि अविकसितता के कारण मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। यह कुछ सरकारों को मानवाधिकारों के उल्लंघन को जारी रखने और मानवाधिकार कानून के तहत अपने दायित्वों की अनदेखी करने की अनुमति दे सकता है। मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार के उद्देश्य से, गैर-सरकारी संगठन अक्सर मानवाधिकार पीड़ितों को कानूनी सहायता (उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत शिकायतों को संभालना), मानवीय सहायता (उदाहरण के लिए, आपातकालीन सहायता, भोजन, पानी, आश्रय, दवा और यातना पीड़ितों के पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य देखभाल) और अन्य प्रकार की प्रत्यक्ष सहायता। गैर-सरकारी संगठनों को मानवाधिकार स्थितियों की जानकारी और निष्पक्षता की प्रतिष्ठा के कारण, कुछ मामलों में गैर-सरकारी संगठन सुलह और मध्यस्थता प्रक्रिया में शामिल होते हैं। आमतौर पर वे राजनीतिक रूप से तटस्थ मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हैं, विरोधी दलों के साथ काम करते हैं, बातचीत की सुविधा देते हैं और दोनों पक्षों के लिए स्वीकृत समाधान खोजने में मदद करते हैं। यह विशेष रूप से उन संघर्षों को सुलझाने का मामला है जहां जातीय अल्पसंख्यक शामिल हैं। मानव अधिकारों के मुद्दों पर शिक्षा स्वयं मानव अधिकारों की स्थिति में सुधार करने में योगदान देती है, क्योंकि लोग अपने अधिकारों के बारे में सीखते हैं और इस प्रकार उन पर दावा करने की संभावना को बढ़ाते हैं। एनजीओ सामान्य रूप से मानवाधिकारों के साथ-साथ विशिष्ट विषयों पर जानकारी का प्रसार करते हैं; वे मानव अधिकारों के विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम आयोजित करते हैं, प्रकाशन जारी करते हैं, और कार्यक्रम (सेमिनार, गोलमेज और आदि) आयोजित करते हैं; और इस तरह एनजीओ मानव अधिकारों के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाते हैं।

अभी भी मानवाधिकारों की रक्षा में मानवाधिकार एनजीओ का सबसे प्रभावी हथियार "शर्म की लामबंदी" या तथाकथित "नामकरण और शर्मनाक" रणनीति का उपयोग है। यह रणनीति मानती है कि किसी देश के मानवाधिकारों के रिकॉर्ड/उसकी अपनी सीमाओं के भीतर दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी का संग्रह और प्रकाशन सरकार को अपने व्यवहार को बदलने में शर्मसार करेगा, सरकार के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के अनुपालन को बढ़ाएगा। यह रणनीति इस विचार पर निर्भर करती है कि सभी सरकारें, दुनिया के सभी देश सभ्य लोगों के रूप में जाना जाना चाहेंगे, जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करते हैं, जिन्हें उन्होंने खुद तैयार करने में मदद की है। कोई भी सरकार आसानी से यह स्वीकार नहीं करेगी कि वह इन मानकों के उल्लंघन की अनुमति देती है। इस प्रकार, इस रणनीति की प्रभावशीलता काफी हद तक एनजीओ द्वारा प्रदान की गई जानकारी की विश्वसनीयता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। "नामकरण और शर्मनाक" रणनीति का उपयोग न केवल देश के भीतर सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है, बल्कि यह आपत्तिजनक शासन के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय जनमत को भी लामबंद कर सकता है, अन्य राज्यों या अंतर-सरकारी संगठनों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे कि खुली आलोचना या कूटनीतिक और "बुरी प्रथा" को बदलने के लिए उल्लंघन करने वाले राष्ट्र के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध। दूसरे शब्दों में मानवाधिकार एनजीओ के काम का एक बाहरी आयाम भी है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सक्रिय गैर सरकारी संगठनों की वकालत के परिणामस्वरूप 1989 में तियानमेन स्क्वायर नरसंहार के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस घटना के बीस से अधिक वर्षों के बाद, "पीपुल्स रिपब्लिक के खिलाफ यू.एस. 1989 में तियानमेन सैन्य कार्रवाई के जवाब में बनाए गए चीन के अधिकार प्रभावी बने हुए हैं, जिसमें कुछ विदेशी सहायता-संबंधी प्रतिबंध शामिल हैं, जैसे कि आवश्यक "नहीं" वोट या चीन को ऋण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के लिए अमेरिकी प्रतिनिधियों द्वारा मतदान से दूर रहना (सिवाय उनके जो बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं) मानव की जरूरत है) "।

## निष्कर्ष

मानवाधिकार एनजीओ कौन हैं: मानवाधिकारों के मुख्य रक्षक या समूह जो राज्य की संप्रभुता को नष्ट करते हैं? उत्तर एक साधारण हां या नहीं की तुलना में अधिक जटिल है, और यह कई अलग-अलग कारकों पर निर्भर करता है जैसे कि देश

के आर्थिक और सामाजिक विकास के स्तर, राजनीतिक शासन, परंपराएं, संस्कृति और साथ ही मानवाधिकार एनजीओ पर सरकार का रवैया और यहां तक कि कैसे राज्य संप्रभुता का आभास होता है। इसका उत्तर काफी हद तक एनजीओ के आकार, प्रकार, शक्ति और सक्रियता पर भी निर्भर करता है। शक्तिशाली, सक्रिय और विश्वसनीय एनजीओ के पास सामान्य मानवाधिकार स्थिति और राज्य की मानवाधिकार नीति को प्रभावित करने की अधिक संभावना है। इस बीच, छोटे और अधिक शक्तिहीन एनजीओ के पास वास्तव में मानवाधिकारों में सुधार करने या राज्य की नीति को बदलने का बहुत कम या कोई मौका नहीं है। इसका मतलब यह है कि एक ही समय में मानवाधिकार एनजीओ मानवाधिकारों के रक्षक और राज्य की संप्रभुता के विध्वंसक हो सकते हैं। सब कुछ उस रवैये पर निर्भर करता है जो एक साथ कई अलग-अलग कारकों से आकार लेता है। परंपरागत रूप से लोकतांत्रिक पश्चिमी देशों में, जहां मानवाधिकारों का सम्मान हावी है, मानवाधिकार एनजीओ को मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में माना जाता है जो मानवाधिकारों के हनन को रोकने या रोकने की कोशिश करते हैं। इस बीच गैर-पश्चिमी देशों में, विशेष रूप से अधिनायकवादी शासनों में, जहां अपेक्षाकृत कम सामाजिक-आर्थिक विकास, कमजोर नागरिक समाज और जहां कभी-कभी लोकतंत्र की कमी होती है, आमतौर पर मानवाधिकार एनजीओ को राज्य की संप्रभुता और राज्य के अधिकार के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। . इन गतिविधियों का देश में मानवाधिकारों की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, मानवाधिकार एनजीओ और राज्य दोनों के रूप में - सिद्धांत रूप में एक ही उद्देश्य है - अर्थात्, मानवाधिकारों को सुनिश्चित करना - मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने में एनजीओ और राज्य / सरकार के बीच प्रभावी सहयोग के लिए पूर्व शर्तों पर आगे का शोध प्रासंगिक है।

## ग्रंथ सूची


[1] बेहर, पीटर आर. "फॉरेन पॉलिसी एक्टर्स एंड ह्यूमन राइट्स": 139-159। इन: इनके बोएरेफ़िज़न और जेनी गोल्डश्मिड्ट, संस्करण। पोल्डर में मानवाधिकार: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में मानवाधिकार और सुरक्षा। एंटवर्प: इंटरसेंटिया, 2007।

[2] बेहर, पीटर आर। "मानवाधिकार एनजीओ और वैश्वीकरण": 31-46। इन: कैरिन आर्ट्स और पास्चल मिह्यो, एड। मानव अधिकारों की कमी का जवाब: बास डे गाय फोर्टमैन के सम्मान में निबंध। क्लूवर लॉ प्रेस, 2013।

[3] बेहर, पीटर आर. "मोबिलाइज़ेशन ऑफ़ द कॉन्शियस ऑफ़ मैनकाइंड: कंडीशंस ऑफ़ इफेक्टिवनेस ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एनजीओज़": 135-155। इन: एरिक डेंटर्स और निको श्रिजवर, एड। पॉल डे वार्ट के सम्मान में निम्न देशों से अंतर्राष्ट्रीय कानून पर विचार। मार्टिनस निझॉफ प्रकाशक, 210।

[4] ब्रह्म, एरिक। "संप्रभुता" // http://www.beyondintractability.org/essay/sovereignty/ (17 अप्रैल, 2011 को देखा गया)।

[5] ब्रेट, राहेल। "मानव अधिकारों के क्षेत्र में गैर-सरकारी अभिनेता": 336- 352। इन: रायजा हंसकी और मरकु सुक्सी, एड। मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण का एक परिचय: एक पाठ्यपुस्तक। मानवाधिकार संस्थान, एबो अकादमी विश्वविद्यालय, 2013 [रूसी संस्करण]।

[6] कलनन, स्कॉट। घरेलू मानवाधिकार एनजीओ की प्रभावशीलता: एक तुलनात्मक अध्ययन। मार्टिनस निझॉफ प्रकाशक, 2018।

[7] क्लाउड, रिचर्ड पियरे। "मानवाधिकार एनजीओ क्या करते हैं?": 424-434। इन: रिचर्ड पियरे क्लाउड एंड बर्न्स एच वेस्टन, एड। विश्व समुदाय में मानवाधिकार: मुद्दे और कार्रवाई। पेन्सिलवेनिया विश्वविद्यालय प्रेस, 2006।

[8] डोनेली, जैक। "राज्य की संप्रभुता और मानवाधिकार" // http://mysite.du.edu/~jdonnell/papers/hrsov%20v4a.htm (23 अप्रैल, 2011 को देखा गया)।

[9] एडवर्ड्स, जॉर्ज ई। "सफल मानवाधिकार गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के गुण - 1948 के साठ साल बाद मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा": 22-26 // http://works.bepress.com/george_edwards/2 / (23 अप्रैल, 2011 को एक्सेस किया गया)।

[10] फ्रीमैन, माइकल ए। "द पॉलिटिक्स ऑफ़ ह्यूमन राइट्स": 156-175। इन: माइकल ए. फ्रीमैन, एड। मानवाधिकार: एक अंतःविषय दृष्टिकोण। राजनीति, 2011।

[11] केक, मार्गरिट ई., और कैथरीन सिक्किंक। एक्टिविस्ट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स: एडवोकेसी नेटवर्क्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2013।

[12] क्लिट्सौनोवा, ऐलेना। "एनजीओ का समर्थन करके रूस में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना: यूरोपीय संघ की रणनीतियों में सुधार कैसे करें।" विदेश और सुरक्षा नीति CEPS कार्य दस्तावेज़ संख्या 287 (अप्रैल 2008): 6–9 // http://www.ceps.eu/files/book/1637.pdf (15 अक्टूबर, 2010 को देखा गया)।

[13] कोरी, विलियम। एनजीओ और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। एक जिज्ञासु अंगूर। पालग्रेव मैकमिलन, 2011।

[14] क्रस्नर, स्टीफन डी। "एबाइडिंग सॉवरेन्टी।" अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान की समीक्षा वॉल्यूम। 22, नंबर 3 (2011): 235–239।

[15] क्रास्नर, स्टीफन डी। "संप्रभुता।" विदेश नीति (जनवरी/फरवरी, 2011): 26।

[16] क्रस्नर, स्टीफन डी। संप्रभुता: संगठित पाखंड। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012।

**[17]** लेक, डेविड ए., और वेंडी एच. वोंग। "द पॉलिटिक्स ऑफ़ नेटवर्क्स: इंटरेस्ट्स, पॉवर, एंड ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स": 127–150। इन: माइल्स कहलर, एड। नेटवर्क्ड पॉलिटिक्स: एजेंसी, पावर और गवर्नेंस। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2015।